Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 109-114

स्वच्छ भारत मिशन और सतत शहरी विकास

राजेश कुमार कुमावत

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत में स्वच्छता को लेकर लंबे समय से सामाजिक, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ विद्यमान रही हैं। इन चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर एक जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया।1 इस अध्ययन का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावशीलता को सतत शहरी विकास के परिप्रेक्ष्य में समझना है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि नीतिगत प्रयास और व्यवहारिक बदलाव किस हद तक शहरी जीवन को प्रभावित कर पाए हैं। यह शोध अनुभवमूलक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता स्थिति, नागरिकों की सहभागिता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जन-जागरूकता अभियानों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन ने शहरी स्तर पर अवसंरचना निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति और कचरा प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु व्यवहारिक परिवर्तन और सतत स्वच्छता प्रबंधन अभी भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अनुसंधान के निष्कर्ष बताते हैं कि केवल नीतिगत ढाँचे और योजनाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते जब तक कि नागरिक सहभागिता और जागरूकता को निरंतर प्रोत्साहित न किया जाए। इस अध्ययन के आधार पर यह सुझाव सामने आता है कि स्वच्छ भारत मिशन को सतत शहरी विकास की दिशा में सफल बनाने के लिए नीतिगत स्पष्टता, व्यवहारिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और दीर्घकालिक प्रबंधन रणनीतियों का समन्वय आवश्यक है।

संकेताक्षर—*स्वच्छ भारत मिशन, शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक सहभागिता, जन-जागरूकता*

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए स्वच्छता केवल स्वास्थ्य या सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि सतत विकास का मूलभूत आधार है। शहरी क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अनियोजित नगरीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जटिलता और नागरिक सहभागिता की कमी ने स्वच्छता को एक गंभीर चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। इन चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य केवल भौतिक अवसंरचना का विकास करना नहीं था, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन लाना भी था।

स्वच्छ भारत मिशन ने शहरी स्तर पर शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच से मुक्ति, और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण जैसी पहलों को गति दी। यद्यपि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हुआ, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप और प्रभाव नगरों में ही दृष्टिगोचर हुआ। शहरी जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को प्रभावित करने वाले तत्वों में स्वच्छता की केंद्रीय भूमिका होने के कारण यह अध्ययन सतत शहरी विकास के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है।

सतत शहरी विकास का तात्पर्य केवल अवसंरचना या आर्थिक प्रगति से नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार,

पर्यावरणीय संतुलन और नागरिक भागीदारी का समावेश होता है। स्वच्छ भारत मिशन इस दृष्टि से एक ऐसी नीति है, जिसने स्वच्छता को व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जोड़ने का प्रयास किया।[2] विशेषतः SDG-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) तथा SDG-11 (सतत शहर एवं समुदाय) के लक्ष्य इस अभियान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।

हालाँकि, नीतिगत स्तर पर किए गए प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब वे व्यवहारिक स्तर पर नागरिकों द्वारा आत्मसात किए जाएँ। यह अध्ययन स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन नीतिगत एवं व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य से करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि शहरी स्तर पर मिशन ने किस प्रकार की ठोस उपलब्धियाँ दीं, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, और सतत शहरी विकास के व्यापक संदर्भ में यह कार्यक्रम किस सीमा तक कारगर सिद्ध हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन का शहरी परिप्रेक्ष्य

स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज का बुनियादी तत्व है, किंतु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। शहरी क्षेत्रों में यह चुनौती और भी गहरी है, क्योंकि तीव्र नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, आवासीय असमानता और अपशिष्ट प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था ने नगरों को अस्वच्छ बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में 2014 में आरंभ हुआ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) न केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में उभरा, बल्कि उसने शहरी स्वच्छता को सतत शहरी विकास के केंद्र में लाने का प्रयास किया।

इस अभियान ने शहरी निकायों को यह अवसर दिया कि वे अपनी स्वच्छता नीतियों और प्रथाओं को पुनः परिभाषित करें। विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घर-घर कचरा संग्रहण, शौचालय निर्माण और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण जैसे क्षेत्रों में इसे एक क्रांतिकारी पहल के रूप में देखा गया। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक विविधता अधिक है, वहाँ इस मिशन का प्रभाव भी बहुआयामी रहा। उदाहरण के लिए, उच्च आय वर्ग के मोहल्लों में कचरा पृथक्करण और रीसाइक्लिंग की प्रवृत्ति तेजी से अपनाई गई, जबकि निम्न आय वर्ग की बस्तियों में खुले में शौच से मुक्ति पर अधिक बल दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ने यह स्थापित किया कि केवल अवसंरचना निर्माण से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक परिवर्तन अनिवार्य हैं। मिशन के पहले पाँच वर्षों में नगरपालिकाओं ने प्राथमिक रूप से अवसंरचना को मजबूत किया- कचरा संग्रहण वाहनों की खरीद, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, और सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। किन्तु जब इन प्रयासों का आकलन किया गया, तो पाया गया कि स्वच्छता की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव लाना आवश्यक है। यही कारण है कि मिशन के दूसरे चरण में जन-जागरूकता अभियान और व्यवहारिक संचार पर अधिक बल दिया गया।

शहरी परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—नगर प्रशासन और नागरिक समाज के बीच का सहयोग। कई शहरों ने स्वच्छता अभियानों को केवल सरकारी पहल के रूप में न चलाकर स्वयंसेवी संगठनों, निजी कंपनियों और नागरिक समूहों को भी शामिल किया। इस प्रकार एक बहु-हितधारक मॉडल विकसित हुआ, जिसने मिशन को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया। उदाहरण के लिए, कुछ नगर निगमों ने "स्वच्छता एप" लॉन्च किए, जिनके माध्यम से नागरिक सीधे गंदगी की शिकायत दर्ज कर सकते थे। इसी तरह कुछ नगरों ने अपशिष्ट पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन राशि अथवा अंक प्रणाली दी।

हालाँकि, इस परिप्रेक्ष्य का एक आलोचनात्मक पक्ष भी है। कई नगरों में मिशन का क्रियान्वयन केवल कागजी आँकड़ों तक सीमित रहा। शौचालयों का निर्माण तो हुआ, लेकिन उनके रख-रखाव की व्यवस्था अपर्याप्त रही। कई जगह घर-घर कचरा संग्रहण तो प्रारंभ किया गया, परंतु पृथक्करण की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अवसंरचना निर्माण और सेवा प्रदायगी के बीच संतुलन स्थापित करना अभी भी एक चुनौती है।

वास्तव में, शहरी स्वच्छता की समस्या गहराई से सामाजिक व्यवहार और प्रशासनिक दक्षता से जुड़ी है। यदि नगर निकाय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करें और नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें, तभी सतत परिणाम संभव होंगे। स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि इसने स्वच्छता को "व्यक्तिगत विषय" से आगे बढ़ाकर

"सार्वजनिक विषय" के रूप में स्थापित किया। पहले जहाँ स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों या नगरपालिका की जिम्मेदारी समझी जाती थी, वहीं अब नागरिकों ने भी इसे अपनी सहभागिता से जोड़ना शुरू किया।

शहरी परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि मिशन ने सतत शहरी विकास के लिए एक आधारशिला रखी। इसने न केवल शहरी अवसंरचना को नया रूप दिया बल्कि समाज में यह धारणा भी उत्पन्न की कि स्वच्छता विकास का अभिन्न अंग है। हालाँकि, इस प्रक्रिया में कई असमानताएँ भी उभरीं। महानगरों में जहाँ संसाधन और तकनीकी विकल्प अधिक उपलब्ध थे, वहाँ मिशन अपेक्षाकृत सफल रहा। लेकिन छोटे और मध्यम शहरों में प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया।

अध्ययन यह इंगित करते हैं कि यदि स्वच्छ भारत मिशन को दीर्घकालिक रूप से सफल बनाना है, तो नगर प्रशासन को नीतिगत कठोरता, वित्तीय पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के साथ-साथ नागरिक सहभागिता को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। यह मिशन केवल शहरी स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।[3]

नीतिगत पहल और नगर प्रशासन की भूमिका

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) केवल एक स्वच्छता कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी नीति है, जिसने शहरी विकास की दिशा और दृष्टि दोनों को प्रभावित किया। वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत के साथ ही इसे प्रधानमंत्री स्तर से सीधे जोड़ा गया, जिससे राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता को बल मिला। मिशन के मुख्य घटकों में शौचालय निर्माण, खुले में शौच से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक कचरा निस्तारण, और जन-जागरूकता अभियान सम्मिलित थे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ढाँचा स्पष्ट किया गया और नगर निकायों को कार्यान्वयन की केंद्रीय इकाई बनाया गया।

भारत सरकार ने इसके लिए नगर निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण प्रदान किया। नगरपालिकाओं के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत स्वच्छता के मानकों को पूरा करने वाले निकायों को प्रोत्साहन राशि दी जाती रही। इसके साथ ही, स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जिसने नगर प्रशासन को नागरिक हितैषी पहले करने हेतु प्रेरित किया।

नीतिगत पहल के तहत नगर प्रशासन को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहली बड़ी चुनौती थी—वित्तीय संसाधनों की कमी। अधिकांश नगर निकाय पहले से ही सीमित बजट और राजस्व आधार के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन जैसे व्यापक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान करना कठिन सिद्ध हुआ। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार से विशेष अनुदान उपलब्ध कराया गया, फिर भी स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नियमित आय स्रोतों का अभाव बना रहा।

दूसरी चुनौती थी—मानव संसाधन और तकनीकी दक्षता की कमी। नगर निकायों के पास पर्याप्त संख्या में स्वच्छता कार्यकर्ता, प्रशिक्षित इंजीनियर, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, कचरा संग्रहण और निस्तारण में तकनीकी खामियाँ सामने आईं। अनेक नगरों में अब भी कचरा डंपिंग ग्राउंड पर ही फेंका जाता रहा, जो सतत शहरी विकास के सिद्धांतों के विपरीत है।

तीसरी चुनौती के रूप में सामने आई—नागरिक सहभागिता की कमी। नीतिगत स्तर पर यह माना गया था कि स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल होगा, जब नागरिक इसमें सक्रिय रूप से सहयोग करें। किंतु नगर प्रशासन ने प्रायः इस पहल को ठेकेदार-आधारित कार्य के रूप में देखा, जिससे नागरिकों के साथ सतत संवाद स्थापित करने में कठिनाई हुई। कई बार देखा गया कि शौचालयों का निर्माण तो हुआ, लेकिन उनका नियमित उपयोग और रख-रखाव सुनिश्चित नहीं हो सका।[4]

स्वच्छ सर्वेक्षण ने भी नगर प्रशासन की भूमिका को अधिक उत्तरदायी बनाया। प्रतिस्पर्धा के चलते नगर निकायों ने नागरिक शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर किया और कई नगरों ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्वच्छता ऐप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी बल्कि नागरिक सहभागिता भी सुलभ हुई।

स्पष्ट है कि नीतिगत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ने नगर प्रशासन को नई दिशा दी। किंतु इसके स्थायित्व की शर्त यह

है कि नगर निकाय केवल सरकारी आदेशों तक सीमित न रहें, बल्कि दीर्घकालिक शहरी स्वच्छता रणनीतियों को अपनाएँ। अन्यथा यह पहल अल्पकालिक उपलब्धियों तक सीमित रह जाएगी और सतत शहरी विकास का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

नागरिक सहभागिता और व्यवहारिक परिवर्तन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे केवल सरकारी योजना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। यह मान्यता रही कि जब तक नागरिक अपने व्यवहार में स्वच्छता को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक अवसंरचनात्मक सुधार टिकाऊ नहीं रह पाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में नागरिक सहभागिता मुख्य रूप से दो स्तरों पर दिखाई दी—

1. सामुदायिक पहलें और स्वयंसेवी संगठन
2. व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन

सामुदायिक स्तर पर अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ, महिला समूह, विद्यालय और स्थानीय सामाजिक संगठन सक्रिय हुए। उन्होंने स्वच्छता रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर अभियानों और जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को प्रेरित किया। कई नगरों में स्वच्छता ऐप और हेल्पलाइन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे नागरिक सीधे नगर निगम को अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकें।

व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो शौचालय उपयोग और कचरा पृथक्करण की आदतें धीरे-धीरे विकसित हुईं। हालाँकि, इस व्यवहारिक परिवर्तन की गति नगर से नगर और वर्ग से वर्ग के अनुसार भिन्न रही। गरीब बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में शौचालयों का उपयोग प्रारंभ में कम रहा, क्योंकि वहाँ पानी और रख-रखाव की सुविधा का अभाव था। दूसरी ओर, उच्च और मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में कचरा पृथक्करण और नियमित डोर-टू-डोर कलेक्शन अधिक सफल रहा।

नागरिक सहभागिता की स्थिति को समझने के लिए मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अखबारों और समाचार चौनलों ने इस अभियान को एक "जन भागीदारी मिशन" के रूप में प्रस्तुत किया। उदाहरण स्वरूप, राजस्थान पत्रिका ने अपने विशेषांक में लिखा कि "स्वच्छ भारत मिशन की असली सफलता नागरिकों के मनोवृत्ति परिवर्तन में निहित है, केवल शौचालय निर्माण में नहीं।"[5] यह दृष्टिकोण बताता है कि मीडिया ने लगातार नागरिकों को सक्रिय रूप से जोड़ने और जागरूक करने का प्रयास किया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तकनीकी पहलें

शहरी स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रही है। भारत के नगर प्रतिदिन लाखों टन ठोस कचरा उत्पन्न करते हैं, जिनका सुरक्षित निपटान नगर निकायों के लिए अत्यंत जटिल कार्य है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने इस दिशा में कई तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलें कीं, जिनका उद्देश्य अपशिष्ट निपटान को वैज्ञानिक और सतत स्वरूप देना था।

(क) घर-घर कचरा संग्रहण—स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निकायों ने डोर-टू-डोर कलेक्शन प्रणाली को प्राथमिकता दी। इस व्यवस्था में विशेष वाहनों को निर्धारित मार्ग पर भेजा गया तथा कई नगरों में वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया। इससे न केवल कचरा समय पर एकत्र हुआ बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी बढ़ा।

(ख) कचरे का पृथक्करण—अभियान की सबसे महत्वपूर्ण पहल 'गीला कचरा-सूखा कचरा' पृथक्करण रही। नागरिकों को दोहरे डस्टबिन (हरा और नीला) दिए गए तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी पृथक्करण की व्यवस्था की गई। तथापि, नागरिकों द्वारा मिश्रित कचरा डालने और निकायों द्वारा पृथक संग्रहण न करने की प्रवृत्ति अब भी बनी हुई है।

(ग) कम्पोस्टिंग और पुनर्चक्रण—मिशन के तहत कई नगरों में स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किए गए। इनसे उत्पादित खाद को नगर निगमों ने उद्यानों तथा कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, सूखे कचरे के पुनर्चक्रण के लिए निजी संस्थाओं के सहयोग से कदम उठाए गए।

(घ) अपशिष्ट से ऊर्जा—कुछ बड़े नगरों ने 'वेस्ट टू एनर्जी' परियोजनाएँ प्रारम्भ कीं, जिनमें ठोस अपशिष्ट से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया अपनाई गई। यह पहल सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसकी सफलता अभी कुछेक महानगरों तक ही सीमित है।

(ङ) प्रमुख चुनौतियाँ—सभी नगरों में पर्याप्त कम्पोस्टिंग या रिसाइक्लिंग यूनिट की उपलब्धता नहीं है।

नागरिक अब भी बड़े पैमाने पर मिश्रित कचरा डालते हैं।

नगर निकायों के पास प्रशिक्षित जनशक्ति और वित्तीय संसाधनों का अभाव है।

(च) समग्र आकलन—अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के बावजूद, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तभी प्रभावी हो सकता है जब नागरिक अनुशासन और जनसहयोग सुनिश्चित किया जाए।[6]

सतत शहरी विकास और स्वच्छ भारत मिशन का योगदान

स्वच्छ भारत मिशन ने शहरी क्षेत्रों में केवल स्वच्छता बढ़ाने तक सीमित न रहकर, सतत शहरी विकास के दृष्टिकोण से बहुआयामी पहल की हैं। सतत शहरी विकास केवल आर्थिक या भौतिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक सहभागिता, पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता का समग्र विकास शामिल होता है।[7]

स्वच्छ भारत मिशन ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएँ संचालित कीं। इनमें सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों का विकास और नगर निगमों के स्वच्छता रैंकिंग कार्यक्रम शामिल हैं। इन पहलों ने न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी योगदान दिया।

शहरी स्तर पर नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक पाई गई। अध्ययन में यह देखा गया कि उन वार्डों और मोहल्लों में जहाँ नागरिक नियमित रूप से कचरा प्रबंधन और सफाई अभियान में सम्मिलित हुए, वहाँ पर्यावरणीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वहीं, जिन क्षेत्रों में नागरिक सहभागिता न्यूनतम रही, वहाँ मिशन के परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सके। यह स्पष्ट करता है कि नीतिगत प्रयास तभी प्रभावी होते हैं जब नागरिकों का व्यवहारिक योगदान उसमें समाहित हो।

स्वच्छ भारत मिशन ने नगर प्रशासन को भी सतत विकास की दिशा में प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया। नगर निगमों ने नियमित निगरानी, डेटा संग्रहण और प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। तकनीकी नवाचार, जैसे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और जीआईएस आधारित निगरानी, ने स्वच्छता प्रयासों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि की।

अध्ययन से यह भी पता चला कि मिशन ने केवल भौतिक अवसंरचना में सुधार नहीं किया, बल्कि शहरी पर्यावरणीय चेतना, सामाजिक अनुशासन और स्वास्थ्य व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाए। उदाहरणस्वरूप, बच्चों और युवाओं के माध्यम से स्वच्छता शिक्षा, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, और स्कूलों में शपथ अभियान ने स्थायी व्यवहारिक परिवर्तन में योगदान दिया।

इस प्रकार यह देखा गया कि स्वच्छ भारत मिशन केवल एक प्रशासनिक या सरकारी पहल नहीं रहा, बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने वाला एक सामुदायिक और व्यवहारिक आंदोलन बन गया।

सुझाव

स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरी भारत में स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता का व्यापक प्रसार हुआ है, किन्तु सतत शहरी विकास की दिशा में इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं—

- स्थानीय निकायों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ किया जाए, ताकि वे स्वच्छता योजनाओं को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वित कर सकें।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- शहरी विद्यालयों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शिक्षा को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए।
- नगरपालिकाओं में सतत निगरानी व्यवस्था और तकनीकी नवाचारों (जैसे डिजिटल अपशिष्ट ट्रैकिंग प्रणाली) को बढ़ावा दिया जाए।
- स्वच्छता अभियानों में महिलाओं, युवाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को स्थायी भागीदारी के रूप में जोड़ा जाए, ताकि यह आंदोलन सामाजिक संस्कृति का अंग बन सके।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन ने भारत के शहरी परिदृश्य में स्वच्छता को केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। इस मिशन के माध्यम से नागरिकों में स्वच्छता के प्रति चेतना और सहभागिता

की भावना बढ़ी है, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। यह पहल नीति, प्रबंधन और व्यवहार-तीनों स्तरों पर परिवर्तन की दिशा में कार्यरत रही है। इस अभियान ने नगर नियोजन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ जल आपूर्ति और स्वच्छ परिवेश के माध्यम से शहरी विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। स्वच्छता को सतत शहरी विकास के साथ जोड़ने से यह स्पष्ट हुआ है कि केवल अवसंरचना निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिक सहभागिता और व्यवहारिक परिवर्तन ही स्थायित्व का आधार हैं।

फिर भी यह भी स्वीकार करना होगा कि अनेक नगरों में संसाधनों की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव और अपशिष्ट पुनर्चक्रण की सीमित व्यवस्था जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए नीति-निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर नवाचार और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। समग्र रूप से देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन ने भारत के शहरी विकास विमर्श को एक नई दिशा दी है- जहाँ स्वच्छता अब केवल भौतिक या सौंदर्यात्मक लक्ष्य नहीं, बल्कि सतत और मानवीय विकास का अभिन्न घटक बन चुकी है। यह अभियान न केवल वर्तमान पीढ़ी के जीवन स्तर को उन्नत करता है, बल्कि भविष्य के शहरी भारत के लिए एक स्वस्थ, पर्यावरण-संवेदनशील और आत्मनिर्भर ढाँचा भी तैयार करता है।

सन्दर्भ सूची

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए दिशा-निर्देश, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2014, पृ.सं. 46-49
2. स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्य, डब्ल्यू.एच.ओ. प्रेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, जेनेवा, 2015, पृ.सं. 71
3. गुप्ता, पी.एन., भारत में शहरी स्वच्छता और सतत विकास की दिशा, शहरी अध्ययन पत्रिका, सेज प्रकाशन, यूनाइटेड किंगडम, 2017, वॉल्यूम-14, अंक-3, पृ.सं. 112-126
4. स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2017, पृ.सं. 34.
5. स्वच्छ भारत की असली सफलता नागरिकों के मनोवृत्ति परिवर्तन में, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 2018, 2 अक्टूबर, पृ.सं. 5
6. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : तकनीक और अनुशासन का समन्वय, इंडिया टुडे, नई दिल्ली, 2019, जून विशेषांक, पृ.सं. 32-36
7. वर्मा, एस.के., सतत शहरी विकास एवं पर्यावरणीय प्रबंधन, ज्ञान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृ.सं. 102-118.